सोने-चांदी में आया ऑल टाइम उछाल

1.55 लाख पर पहुंचा सोना

3.19 लाख पार पहुंची चांदी

नई दिल्ली 23 जनवरी. सोना-चांदी के दामों ने 23 जनवरी 2026 को नए रिकॉर्ड स्तर को पार कर लिया. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 4,300 बढ़कर 1,55,428 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया. वहीं 1 किलो चांदी 19,249 उछलकर 3,18,960 हो गई.

इस साल सिर्फ 23 दिनों में सोना 22,233 और चांदी 88,540 महंगी हो चुकी है. विशेषज्ञों का कहना है कि सोने की बढ़ती कीमतों के पीछे वैश्विक तनाव, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होना और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी प्रमुख कारण हैं. निवेशक अब सुरक्षित निवेश यानी सोने और चांदी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. इंडस्ट्रियल मांग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी सेक्टर की आवश्यकता ने चांदी को ज्वेलरी से बढ़कर जरूरी कच्चा माल बना दिया है. यदि अमेरिकी टैरिफ और मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ता है तो सोना रुपए 1.90 लाख और चांदी 4 लाख प्रति किलो तक जा सकती हैं. साल 2025 में भी सोना 75प्रतिशत और चांदी 167प्रतिशत महंगी हुई थी. बसंत पंचमी के मौके पर इन ऐतिहासिक भावों ने निवेशकों और आम लोगों की नजरों को आकर्षित किया है.

सोना-चांदी निवेश में कौन सा देश सबसे आगे है – विश्व में सोने का सबसे बड़ा भंडार अमेरिका के पास है, जबकि रूस और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख उत्पादक हैं. भारत और चीन सोने के सबसे बड़े निवेशक हैं. चांदी उत्पादन में मेक्सिको और पेरू आगे हैं, जबकि भारत और चीन इसके बड़े उपभोक्ता हैं.

सोना-चांदी दाम बढ़ने के 4 प्रमुख कारण

1. सबसे महत्वपूर्ण कारण सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग है. जब वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं, जैसे युद्ध, व्यापार युद्ध या टैरिफ, तो निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए सोना और चांदी जैसी भौतिक संपत्तियों में लगाते हैं.
2. डॉलर की कमजोरी है. डॉलर कमजोर होने पर सोना और चांदी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में महंगा हो जाता है. भारतीय रुपये की कमजोरी के कारण आयातित सोने-चांदी की लैंडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे घरेलू बाजार में भी कीमतें ऊपर चली जाती हैं.
3. औद्योगिक मांग और आपूर्ति में कमी है. इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सेक्टर में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है. वहीं, उत्पादन और रीसाइक्लिंग में कमी ने सप्लाई और मांग के बीच अंतर और बढ़ा दिया है.
4. केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और मुद्रास्फीति का डर है.

वेतन और पेंशन संशोधनों को मिली मंजूरी

नई दिल्ली, 23 जनवरी. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए व्यापक वेतन एवं पेंशन संशोधनों को मंजूरी प्रदान की. यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों , राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा तथा पूर्व कर्मचारियों की आर्थिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है.

केंद्र सरकार के इस संशोधन से कुल मिलाकर लगभग 46,322 कर्मचारी; 23,570 पेंशनर; और 23,260 परिवार पेंशनर लाभान्वित होंगे. वित्त मंत्रालय की कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन एक अगस्त 2022 की पूर्ववर्ती तिथि से लागू होगा. इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता में 14 प्रतिशत वृद्धि की गई है, जिससे कुल वेतन खर्च में 12.41 प्रतिशत वृद्धि होगी. इसके अलावा जो एक अप्रैल 2010 के बाद जुड़े कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में कर्मचारियों का योगदान 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है. परिवार पेंशन में भी 30 प्रतिशत की एक समान वृद्धि की गई है, जो आधिकारिक गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी. इन संशोधनों से पीएसजीआईसी पर 8,170.30 करोड़ रुपये का वित्तीय असर पड़ने का अनुमान है.

पीएसजीआईसी में जो प्रमुख बीमा कंपनियां शामिल हैं उनमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी शामिल हैं.

भारत बनेगा 2035 तक सेमीकंडक्टर विनिर्माता देश

दावोस (स्विट्जरलैंड)/नई दिल्ली, 23 जनवरी. इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में सेमीकंडक्टर और माइक्रो चिप विनर्माण उद्योग के विकास की दिशा में प्रगति को महत्वपूर्ण बताते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि 2025 तक भारत की गिनती सेमीकंडक्टर के क्षेत्र के प्रमुख देशों में होगी.

विश्व आर्थिक मंच की दावोस बैठक में भाग लेने गये श्री वैष्णव ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि इस क्षेत्र में देश ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं.उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मानव जाति के अब तक के सबसे जटिल कार्यों में से एक है. भारत में इसके लिए बहुत सूक्ष्मता और व्यवस्थित तरीके से विनिर्माण श्रृंखला और पूरे विनिर्माण तंत्र के विकास पर काम किया गया है. उन्होंने कहा देश में योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पहले 28 नैनोमीटर के चिप से काम की शुरुआत हो रही है. उसके बाद क्रमश- 7 नैनोमीटर, 3 और फिर 2 नैनोमीटर तक जाया जाएगा. उन्होंने कहा, वर्ष 2035 तक भारत दुनिया के प्रमुख सेमीकंडक्टर देशों में से एक बन जाएगा. रेलवे और सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी दायित्व संभाल रहे श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में जिन 10 कारखानों को लगाने को मंजूरी दी है उनमें चार ने पिछले कुछ महीनों में परीक्षण के तौर पर विनिर्माण शुरू कर दिया है.

वैष्णव ने दावोस में एआई क्षेत्र की हस्तियों से की मुलाकात

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैषणव ने स्विट्जरलैंड के दावोस में गूगल डीपमाइंड के मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) और सह-संस्थापक डेमिस हासाबिस और ओपेन एआई के वैश्विक मामलों के मुख्य अधिकारी क्रिस लेहने से अलग-अलग मुलाकात की. श्री वैष्णव लेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ रेलवे और सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. वह दावोस में गैर सरकारी संगठन विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में भाग लेने गये हैं.

विदेशी मुद्रा भंडार में 14.17 अरब डॉलर का बड़ा उछाल

मुंबई, 23 जनवरी. विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और स्वर्ण भंडार में तेज वृद्धि के कारण देश का विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 14.167 अरब डॉलर बढ़कर 17 अक्टूबर 2025 के बाद के उच्चतम स्तर 701.36 अरब डॉलर पर पहुंच गया. विदेशी मुद्रा के देश के भंडार का यह 07 मार्च 2025 के बाद का उच्चतम स्तर है. आलोच्य सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में 9.652 अरब डॉलर की वृद्धि हुई और इसका स्तर 560.518 अरब डॉलर दर्ज किया. इसमें अमेरिकी डॉलर के अलावा यूरो, जापानी येन और ब्रितानी पाउंड भी शामिल हैं जिनका मूल्य डॉलर की तुलना में उनके संदर्भ दर के आधार पर तय होता है.

रिजर्व बैंक ने खरीदी 50,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां

मुंबई, 23 जनवरी. रिजर्व बैंक ने गुरुवार को खुले बाजार से 50,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदीं. केंद्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के पास नकदी की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों के तहत यह खरीद की है. यह चार समान किस्तों में दो लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के तहत अंतिम किस्त है.

रिजर्व बैंक ने बताया गया है कि उसने सात तरह की प्रतिभूतियों की खरीद की है जिनकी मियाद साल 2029 से 2054 तक अलग-अलग समय पर पूरी हो रही हैं. इसमें तीन साल, पांच साल, सात साल, आठ साल, नौ साल, 10 साल और 28 साल की प्रतिभूतियां शामिल हैं. इन प्रतिभूतियों पर 6.10 प्रतिशत से 7.57 प्रतिशत का ब्याज दिया गया है. सबसे अधिक 26,425 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां साल 2029 की मियाद वाली हैं जिन पर 7.10 प्रतिशत ब्याज मिलेगा.

पहली किस्त में 50 हजार करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां 29 जनवरी को खरीदी गयी थीं. दूसरी किस्त के तहत 05 जनवरी को और तीसरी किस्त के तहत 12 जनवरी को खरीद की गयी थी. दिसंबर में इससे पहले भी दो समान किस्तों में केंद्रीय बैंक ने एक लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की थी.

अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्स . 20 कोच के साथ चलेगी ट्रेन

अहमदाबाद, 23 जनवरी. पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 22961/22962 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से 4 अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया गया है.

यह ट्रेन दिनांक 26 जनवरी 2026 से 07 मार्च 2026 तक वर्तमान 16 कोचों के स्थान पर 20 कोच (20 के साथ संचालित की जाएगी. इस वृद्धि के अंतर्गत मौजूदा सी14 कोच की क्षमता 44 सीटों से बढ़ाकर 78 सीटें की जा रही है. इसके अतिरिक्त चार नए एसी चेयर कार कोच सी 15, सी16, सी17 (प्रत्येक 78 सीटें) तथा सी18 (44 सीटें) ट्रेन संरचना में जोड़े जा रहे हैं. इस तरह इस ट्रेन में 278 यात्री अधिक यात्रा कर सकेंगे. पश्चिम रेलवे यात्रियों को अधिक सुविधा, आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयासरत है.

रुपया पहली बार 92 प्रति डॉलर तक टूटा

मुंबई, 23 जनवरी. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया शुक्रवार को कमजोर हुआ और पहली बार एक डॉलर 92 रुपये का बोला गया. भारतीय मुद्रा गुरुवार को 91.58 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी. यह सुबह 13 पैसे की मजबूती के साथ 91.45 रुपये प्रति डॉलर पर खुली और 91.41 रुपये प्रति डॉलर तक चढ़ी. लेकिन इसके बाद दबाव बढ़ता गया और यह 42 पैसे की गिरावट में 92 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गयी.अंतिम आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल रुपया 30 पैसे की गिरावट में 91.88 रुपये प्रति डॉलर पर था.

गोल्ड लोन एनबीएफसी एयूएम 4 लाख करोड़ पार

नई दिल्ली, 23 जनवरी. क्रिसल रेटिंग्स के अनुसार सोना रख कर कर्ज देने के कारोबार पर केंद्रित गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) मार्च 2027 तक चार लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा होने का अनुमान है.

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार गोल्ड लोन कारोबार में तेजी जिसका मुख्य कारण सोने की ऊंची कीमतें, सिक्योर्ड क्रेडिट की बढ़ती मांग और रेगुलेटरी सुधार हैं. क्रिसिल की गुरूवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह बढ़ोतरी सोने की ऊंची कीमतों, सिक्योर्ड क्रेडिट की ओर बदलाव और बेहतर रेगुलेटरी माहौल के कारण होगी. इस वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में सोने की कीमतें 68 प्रतिशत बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं. इससे गिरवी रखी गई चीज़ों का मूल्यांकन बढ़ा है और कर्ज बांटने में आसानी हुई है.

गृह मंत्री अमित शाह ने किया क्रिटिकल हॉस्पिटल का लोकार्पण

हरिद्वार। पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित विश्व के प्रथम इंटीग्रेटेड मैडिसिन सिस्टम तथा योग, आयुर्वेद व आधुनिक चिकित्सा के समन्वय का वैश्विक केंद्र पतंजलि इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल समस्त भारत के नागरिकों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करेगा।

गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उक्त हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हास्पिटल का निरीक्षण भी किया और इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम की इस पहल को सराहा। उन्होंने कहा कि यह हॉस्पिटल विश्व का प्रथम हाइब्रिड हॉस्पिटल बन गया है। ज्ञात हो कि गृह मंत्री जी दो दिनों के पतंजलि प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने योग, आयुर्वेद व सनातन जीवन पद्धति को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठापित करके रोगमुक्त विश्व का निर्माण कैसे हो, इस पर पूज्य स्वामी जी के साथ गहन विमर्श व मंथन किया।

गृहमंत्री ने पतंजलि योगपीठ परिसर में आत्मीयतापूर्ण रात्रि विश्राम किया और चिकित्सा, शिक्षा, सनातन जीवन पद्धति, एवं ऋषियों की ज्ञान विरासत को विश्व पटल पर प्रतिष्ठा दिलाने की दिशा में पूज्य स्वामी रामदेव जी एवं आचार्य बालकृष्ण महाराज से विमर्श एवं विचार मंथन किया और पतंजलि द्वारा भविष्य में इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने के बारे जानकारी ली। उनके आत्मीय आगमन से पतंजलि परिवार में गौरव, प्रेरणा और ऊर्जा का संचार हुआ.

समाचार विशेष

हमारे राम...के जरिये हिंदू वोट बैंक साधेगी आप

सरकार की पंथक राजनीति की रणनीति ; कई जिलों में 40 शो

चंडीगढ़. आम आदमी पार्टी (आप) अब पंजाब में हमारे राम... थियेटर शो के जरिये हिंदू वोट बैंक को साधेगी. पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अंतर्गत सरकार प्रदेश में हमारे राम... के 40 शो करवाएगी. ये शो विभिन्न जिलों में आयोजित करवाए जाएंगे.

राजनीतिक मामलों के जानकारों की मानें तो यह फैसला आप सरकार की पंथक राजनीति की रणनीति का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से पार्टी सूबे में हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में

करने की कोशिश करेगी. पंजाब में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो श्री राम में अपनी गहरी आस्था रखती है. सरकार भी पंजाब में सभी धर्मों, पंथों, जातियों और बिरादरियों का मान-सम्मान करते हुए मतदाताओं में अपनी पैठ बढ़ा रही है.

अभी तक पंजाब में पंथक राजनीति के लिए शिरोमणि अकाली दल को ही सबसे बड़ा रणनीतिकार दल समझा जाता था, मगर उनकी पंथक राजनीति एक विशेष वर्ग के मतदाताओं के इर्द-गिर्द ही घूमती है. आम आदमी पार्टी ने इस फैसले के साथ यह दिखा दिया है कि वह सूबे में अपनी पंथक राजनीति को और धार देते हुए आगे बढ़ रही है. सभी धर्मों, पंथों, जातियों और बिरादरियों को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए पार्टी ने जाति आधारित विभिन्न प्रकोष्ठ गठित किए हुए हैं, जिनके सलाह-मशवरा के बाद विभिन्न वर्गों की कल्याणकारी नीतियां बनाई जाती हैं.

श्री राम सभी के आराध्य- चीमा

पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा कहते हैं कि श्री राम सभी के आराध्य हैं. उनके आदर्श और उनकी मर्यादाएं हमारी जीवनशैली और कार्यशैली को सुधारने व उसे अनुशासित बनाने में बहुत मदद करती हैं. इसलिए सरकार चाहती है कि हमारे राम... के माध्यम से लोगों तक भी श्री राम जी के जीवन का संदेश पहुंचाया जाए. इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक में इस संदर्भ में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

कांग्रेस और लेफ्ट कैच 22 सिचुएशन में

नई दिल्ली. कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां चिंता में हैं. उनको तय करना है कि पश्चिम बंगाल और केरल के विधानसभा चुनाव में क्या करना है. यह कैच 22 सिचुएशन है, जिसे हिंदी में सांस छुछुंदर वाली गति कहते हैं. पिछली बार कांग्रेस और लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल में मिल कर चुनाव लड़ा था और केरल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे. इसका कोई फायदा पश्चिम बंगाल में तो नहीं हुआ लेकिन केरल में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो गया. पांच साल विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी को लेकर पूरे भरोसे में थी क्योंकि केरल में हर पांच साल में सत्ता बदलती है. लेकिन 2021 में पांच साल पर सत्ता बदलने का रिवाज बदल गया. वामपंथी पार्टियों का मोर्चा लगातार दूसरी बार सत्ता में आ गया. कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि उस समय यह मैसेज हो गया कि कांग्रेस और लेफ्ट एक ही हैं. इसलिए दिल्ली के लिए कांग्रेस को और केरल के लिए लेफ्ट को चुनने का फैसला कर लिया लोगों ने.

बंगाल में बीजेपी की राह आसान करेंगे मुस्लिम !

कोलकाता. पश्चिम बंगला विधानसभा चुनाव की चर्चाएं देशभर में हो रही हैं. चुनाव थोड़ा दूर है, लेकिन राजनीति के पहिए तेज रफ्तार से घूम रहे हैं. यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि ममता बनर्जी के उस सामाजिक मॉडल की अग्निपरीक्षा है, जिसने एक दशक से अधिक समय तक प्रदेश की राजनीति को दिशा दी.

मार्च-अप्रैल में संभावित चुनाव और 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ राज्य की राजनीति दो स्पष्ट ध्रुवों- टीएमसी और बीजेपी में सिमटती जा रही है.

ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे स्थायी आधार महिलाएं हैं. इसका कारण लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपश्री, आनंदधारा और सबला आदि योजना हैं. इन योजनाओं ने सरकार और महिला मतदाता के बीच मजबूत संबंध बनाया है. 2024 के लोकसभा चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के करीब बराबर रही थी. यह वह सामाजिक सच्चाई है, जिसने ममता को लगातार बढ़त दिलाई. लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं

अब कल्याण नहीं, बल्कि चुनावी सुरक्षा कवच हैं. बंगाल में आज चुनावी गणित नहीं, महिला मनोविज्ञान सत्ता तय कर रहा है. यही वजह है कि चुनाव से पहले महिलाओं के लिए नई या संशोधित योजना की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

नीतीश कुमार मॉडल का बंगाल संस्करण- महिला सशक्तीकरण के माध्यम से सत्ता का सामाजिक आधार मजबूत करने की यह रणनीति बिहार में नीतीश कुमार द्वारा अपनाई गई थी. जीविका दीदियां, आरक्षण, छात्रवृत्ति ने बिहार की सत्ता को स्थायित्व दिया. बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने इसी मॉडल को बंगाल की जरूरतों के मुताबिक ढालते हुए आधी आबादी को अपना कोर वोट बैंक बनाया.

भाजपा के पास मजबूत नैरेटिव, पर कमजोर स्थानीय चेहरा

2021 में बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर साफ कर दिया था कि बंगाल एकतरफा मैदान नहीं रहा. पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, हिंदुत्व का एजेंडा, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और एसआईआर जैसे मुद्दों ने बीजेपी को वैचारिक ऊर्जा दी है. हाल के विधानसभा चुनावों में मिली सफलता से बीजेपी का आत्मविश्वास और बढ़ा है. मगर, बीजेपी की चुनौती है कि बंगाल में उसका चेहरा अब भी राष्ट्रीय है. कोई स्थानीय नहीं. यह अंतर चुनावी मोड़ पर निर्णायक बन सकता है.

विशेष | मुस्लिम और दलित वोट पर हो सकती है सेंधमारी

मोदी-योगी नहीं, अखिलेश को दो नेताओं का डर

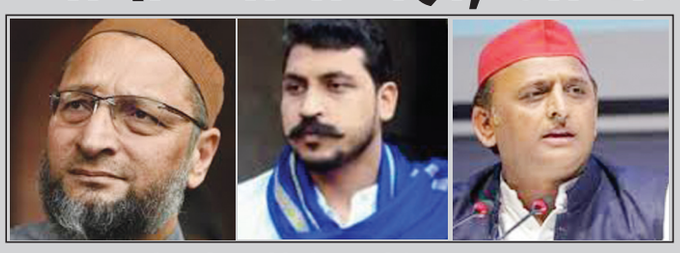

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक दल अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के भीतर एक तरह की बेचैनी और चिंता साफ नजर आने लगी है.

बदलते सियासी समीकरणों और नए चेहरों की सक्रियता ने पार्टी नेतृत्व को गंभीर मंथन के लिए मजबूर कर दिया है.

इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई. बैठक का औपचारिक एजेंडा पंचायत चुनावों की तैयारी और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना था, लेकिन चर्चा के दौरान दो नाम बार-बार उभरकर सामने आए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद.

ओवैसी-आजाद फैक्टर पर बढ़ी मुश्किलें- सांसदों ने इन दोनों नेताओं की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता को लेकर गहरी चिंता जाहिर की. महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव और बिहार के हालिया चुनावी नतीजों का हवाला देते हुए कहा गया कि ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पकड़ को और मजबूत किया है. कभी मुंबई में मुस्लिम समाज के बीच मजबूत मानी जाने वाली सपा को बीएमसी चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि ओवैसी की एआईएमआईएम ने वहां अपनी प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज कराई. इस बदलाव ने सपा को मुस्लिम वोट को लेकर बैकफुट पर ला खड़ा किया है. बैठक में एक सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी का बढ़ता प्रभाव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी है. वहीं दूसरे सांसद ने चंद्रशेखर आजाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वे सपा के स्थानीय नेताओं और समर्थकों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, जिससे पार्टी की जमीनी पकड़ कमजोर हो सकती है.

अखिलेश ने तैयार की रणनीति

हालांकि, अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को आश्वस्त किया कि समय आने पर इन चुनौतियों से निपटने की ठोस रणनीति बनाई जाएगी. बैठक के बाद नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर ओवैसी का नाम लेने से बचने की कोशिश की, लेकिन उनके बयानों में 'पीडीए' यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एकता पर खास जोर दिखा. संकेत साफ है कि सपा बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में साथ आने वाले सभी दलों के लिए दरवाजे खुले रखना चाहती है. अखिलेश यादव ने सांसदों को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच सक्रिय होने का निर्देश भी दिया है.